you are asking about the economic situation over there and what kind of assistance will be given to Orissa, this issue will be discussed between the Planning Commission and the Government of Orissa and the Government of India. It will not be possible for me from the Home Ministry to reply to this kind of omnibus question.

Assistance by International agencies

*305. PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA:†
SHRI RAJU PARMAR:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether international agencies like World Bank and Asian Development Bank are assisting the State Governments for drinking water and sanitation schemes;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Central Government is also providing financial assistance for drinking water and sanitation in various States including Gujarat under some guidelines; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

(a) and (b) So far only the World Bank, from amongst the international multilateral agencies, has been providing assistance to the State Governments for projects in rural water supply and sanitation sector (RWSS). The World Bank has so far provided assistance to four States viz. Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh and Kerala. Till date, three World Bank funded RWSS projects in Maharashtra, Karnataka and Uttar Pradesh have been completed wherein World Bank provided $ 241.90 million against the total project cost of $ 329.60 million. Presently, there are three on-going World Bank funded RWSS projects in Kerala, Karnataka and Maharashtra. The total estimated cost of these on-going projects is $ 551.89 million of which the World Bank share is $ 398.10 million.

(c) and (d) Government of India has been providing assistance to the State Governments and Union Territories in the drinking water and sanitation sector through funds under various components of the Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) and Total Sanitation Campaign (TSC).

†The Question was actually asked on the floor of the House by Prof. Alka Balram Khatriya.

While allocation of funds among States/UTs under various components of ARWSP is based on inter-State allocation ratio fixed for the year after giving weightage to rural population, States under DDP, DPAP, HADP and Special Category Hill States in terms of rural areas, NC/PC habitations and Quality affected habitations as stipulated in ARWSP Guidelines, there is no State/UT wise allocation under TSC as it is a demand-driven scheme. Details of funds released to States/UTs, including Gujarat, under rural drinking water supply programmes in 2004-05 and TSC (till 15.12.2004) are enclosed at Statement I

Statement-I

Details of funds released to State/UTs under Rural Drinking Water Supply Programmes

(Rs. in lakh)

S No	State/UT	Funds released under	
		Rural Drinking Water Programmes during 2004-05 (as on 15.12.04	Total Sanitation Campaign (cumulative upto 15 12 2004)
1	2	3	4
1	Andhra Pradesh	21579 24	11999.10
2.	Bihar	6207 53	4051 48
3.	Chhattisgarh	1979.65	1405 14
4	Goa	0.0	124 67
5.	Gujarat	7844 46	4171 44
6	Haryana	1671.34	1662.38
7.	Himachal Pradesh	3463 71	132.81
8.	J & K	10042 01	1163.26
9	Jharkhand	2903 28	1624.93
10.	Karnataka	11461.99	758.04
11.	Kerala	3697 32	2978.64
12.	Madhya Pradesh	6483 57	8187.23
13.	Maharashtra	16658 94	6972.76
14.	Orissa	6605.55	6203.32
15.	Punjab	2110.91	959 03
16.	Rajasthan	23254.63	2356.26
17.	Tamil Nadu	11659 47	9418 17
18.	Uttaranchal	2449.99	702 41
19.	Uttar Pradesh	11312 3	11475 06

1	2	3	4
20	West Bengal	9473.5	6418 98
21	A & N Islands	0.0	0
22	Chandigarh	0.0	0
23.	D & N Haveli	26 23	3.15
24.	Daman & Diu	0.0	0
25	Delhi	0.0	0
26.	Lakshadweep	0.0	0
27.	Pondicherry	0.0	94.84
28.	Arunachal Pradesh	6946.6	152.26
29.	Assam	8546.61	742.91
30.	Manipur	1147	151.64
31.	Meghalaya	1778.71	221.37
32.	Mizoram	1092.52	11.51
33	Nagaland	978.01	132.12
34	Sikkim	767.29	272.81
35	Tripura	1609 76	1940.72
	TOTAL:	183752 12	86488.44

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: सभापति महोदय, पिछली एन॰डी॰ए॰ सरकार ने तीन साल के लिए गुजरात राज्य के सूरत, राजकोट और मैं जहां से आती हूं - मेहसाना जिले के अंदर एक योजना सैक्टर रिफॉर्म करके पीने के पानी की चालू की थी। उसमें 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती थी और 10 प्रतिशत पब्लिक कंट्रिब्यूशन होता था। वहां गवर्नमेंट ने एक परिपत्र भेजा जिसमें लिखा गया था कि एड्होक बेस पर सरकार 40 करोड़ रुपया ही इस योजना के लिए देती है। तो वह 40 करोड़ और उसमें 4 करोड़ का पब्लिक कांट्रिब्यूशन मिलाकर कुल 44 करोड़ के अंदर 320 गांवों में पानी दिया गया और वह काम पूरा भी हो गया। उस योजना की मियाद 2004 तक पूरी होती थी।

श्री सभापति: आप पूछ क्या रही हैं?

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : इससे पहले यानी कि 31-5-2003 को बाकी के 170 गांवों के अंदर यह मंजूरी दे दी गई, इसके लिए प्लान और एस्टीमेट भी तैयार कर दिए।

श्री सभापति : प्रश्न करें।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : वही तो मैं प्रश्न कर रही हूं। लेकिन बाद में सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। अब मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि जिस गांव में पैसे वाले लोग थे, वहां तो काम पहले पूरा कर दिया गया, लेकिन जो गरीब लोगों के गांव थे, जिन्होंने बाद में पैसे दिए, उन लोगों के लिए क्या मंत्री जी पैसे एलौट करेंगे या वे भी एन॰डी॰ए॰ सरकार की ही तरह गरीब लोगों के गांव वालों को भूखा प्यासा मारेंगे? कम से कम पानी तो दीजिए, वहां के लोगों को ...(व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, पीने के पानी की सैक्टर रिफॉर्म योजना देश के 67 जिलों में लागू की गई थी, जिसमें सूरत के बारे में माननीय सदस्या ने उल्लेख किया है। अब वह सैक्टर रिफॉर्म योजना खत्म कर दी गई है और अब स्वजल धारा उसी की तरह की यह योजना है, कोई बहुत फर्क नहीं है। महोदय, केवल एक ही फर्क है उसमें और वह फर्क यही है कि पहले गांव की कमेटियां बनती थीं तथा उनके द्वारा योजना कार्यान्वित होती थी जबकि स्वजल धारा में सारी चीजें वही हैं, अब केवल पंचायती राज के द्वारा वह योजना लागू की जा रही है। महोदय, उसमें वही फार्मूला है कि गांव के लोग 10 प्रतिशत लागू करें 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार देगी। 10 डग गांव के लोग चलें, 90 डग सरकार चलेगी। तो पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्या ने जो चिंता जाहिर की है, उसके लिए कोई भी उपाय किया जायेगा, गांव के लोगों को शुद्ध पानी, केवल पानी नहीं, शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध कराने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। उनका जो गांव बचा हुआ है, उसको स्वजल-धारा में परिणत करके पूरी सहायता की जायेगी, जिससे वहां के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सके।

श्री सभापति : अब क्या क्वेश्चन है, आप शुद्ध पानी पीओ। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : सभापति महोदय, उन्होंने स्वजल-धारा के बारे में कहा है। स्वजल-धारा में जो फंड दिया जाता है, वह कम है। अगर उसी फंड से यह काम चला, तो 35 साल बाद पानी मिलेगा। इसलिए मैं विशेष प्रावधान चाहती हूं। यह स्वजल-धारा के तहत नहीं, इसके लिए कोई विशेष योजना बनाई जाये, जो 170 गांवों के लोगों को मंजूरी दे दी गई है, फिर उससे पिछली सरकार मुकर गई।

श्री सभापति : क्या कोई विशेष योजना बनाने का विचार है? बस आपका क्वेश्चन हो गया। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : सर, मेरा दूसरा सवाल है।

श्री सभापति : दूसरा सवाल नहीं। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : सर, मुझे दूसरा सवाल करने दीजिए।

श्री सभापति : इतनी देर से क्या कर रही थीं?

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : सर, यह पहला सवाल था, मैं उसी के बारे में यह पूछ रही थी। दूसरा मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है। ...(व्यवधान)... केन्द्र सरकार गांव के लोगों को जो पैसा अलग-अलग योजनाओं के तहत मुहैया कराती है। मैं पीने के पानी की खास बात कर रही हूं। इसकी जो कमेटी बनाई जाती है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप क्वेश्चन कीजिये। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : सर, मैं सीधा क्वेश्चन कर रही हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : ठीक है। आप क्वेश्चन करिये। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : सर, मैं मंत्री जी की तरफ क्यों देखूंगी, मैं आपकी तरफ ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : मैं भी जवाब दे दूंगा, लेकिन आप इनसे सवाल कर लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : सर, जो कमेटी बनाई जाती है, क्या उस कमेटी के अंदर जिला पंचायत के मेम्बर को या लोकल एम॰ पी॰ को आप रखना चाहते हैं, क्योंकि वह कमेटी ठीक नहीं चलती है? मैं अपने यहां की बात करना चाहती हूं कि हमारे यहां स्वजल-धारा के अंदर, सम्पूर्ण स्वरोजगार योजना ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। अब मुझे कहना पड़ेगा कि लिखा नहीं जायेगा। ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : ग्राम स्वरोजगार योजना है, उसके पैसे से ...(**व्यवधान**)... सर, आप सुन लीजिये। उस पैसे से गरीब लोगों को रोजगार देने के बजाय, ठेकेदारों को ठेका दिया गया और वह काम करवाया गया। क्या यह सरकार ठेका देने वालों के लिये है या गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए है? मंत्री जी इसकी जांच-पड़ताल करवायें। गुजरात सरकार ने गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ी *की है।

श्री सभापति : ठीक है। ठीक है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, जो जिला स्तर पर संकल्प समिति है, संकल्प बना हुआ है, उसमें माननीय एम॰ पी॰ साहब भी सदस्य हैं, उनको कोई ...(**व्यवधान**)...

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : हमारे यहां एम॰ पी॰ सदस्य नहीं हैं। जिला पंचायत के प्रमुख को भी सदस्य नहीं बनाया गया है। इसकी जांच करवाई जायें ...(**व्यवधान**)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सर, कोई स्पेसिफिक शिकायत माननीय सदस्या करें, तो उसकी छानबीन हम करेंगे, जांच पड़ताल करवायेंगे। ...(**व्यवधान**)... उसकी जांच-पड़ताल करवायेंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : श्री राजू परमार। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सर, महिला सदस्या के साथ ऐसा किया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

---

*Expunged as ordered by the Chair.

प्रो॰ अलका क्षत्रिय : स्वजल-धारा के पैसे से ...(व्यवधान)... गरीबों के पैसे लोगों को बांटे जाने हैं, इसकी मंत्री जी जांच-पड़ताल करवाइये। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : अब आप बैठ जाइये। आपका क्वेश्चन हो गया है। ...(व्यवधान)... श्री राजू परमार।

श्री राजू परमार : चेयरमैन साहब, जैसा हमारी सदस्या प्रो॰ अलका जी ने बताया कि केन्द्र सरकार की तरफ से रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत जो फंड अभी रिलीज किया गया है 7844.46 रुपये, जैसा माननीय सदस्या ने बताया कि पूरे नार्थ गुजरात में और पूरे सौराष्ट्र में पानी की किल्लत है, वहां पर काफी सूखा भी पड़ता है और वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की खास प्राब्लम होती है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो आपने फंड अलोकेट किया है, यह बहुत ही कम है, क्योंकि नार्थ गुजरात और पूरे सौराष्ट्र में हर बार सूखा पड़ता है, तो उसके बारे में क्या आप इस फंड को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, अभी दो योजनाएं पीने के पानी के संबंध में हैं, Accelerated Rural Water Supply Programme और स्वजल-धारा दो तरह की योजनाएं अभी चल रही है। लेकिन पहले राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन था, उसको पुरानी सरकार ने खटाई में डाल दिया था ...(व्यवधान)...महोदय, उसको हम फिर रिवाइव कर रहे हैं। देशभर में जहां एवेलिबिलिटी आफ वाटर नहीं है। ...(व्यवधान)... महोदय, शुद्ध पानी की उपलब्धता नहीं है, उसके लिए सब मिशन था, उसको हम रिवाइव करने जा रहे हैं और उसके लिए वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल फंडिंग करके राशि की कमी न हो, इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किया जायेगा। इसमें गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश शामिल है। महोदय, यहां क्वालिटी की भी समस्या है ...(व्यवधान)... पानी की अनुपलब्धता है, उपलब्धता की भी समस्या है, उन दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए हम कृत संकल्प हैं। हर तरह से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : नेक्स्ट, डा॰ कुमकुम राय। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया : सर, इन्होंने कहा है कि योजना में खटाई डाल दी है या तो ये उसमें चासनी डाल दें या गुड़ वाली मिठाई डाल दें। ...(व्यवधान)...

खेल अकादमी खोला जाना

***306. डा. कुमकुम राय:** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में संसाधनों की कमी को देखते हुए खेल मंत्रालय ने एक खेल अकादमी खोलने की योजना बनाई थी;